भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2707

04 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: **मसूर की खेती और उत्पादन**

2707. डॉ. आनन्द कुमारः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश का बहराइच जिला पूर्व में देश में मसूर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, जहां उच्च गुणवत्ता वाली तथा पौष्टिक मसूर का उत्पादन किया जाता था, किन्तु विगत कुछ वर्षों के दौरान मसूर की खेती और उत्पादन में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने जलवायु परिवर्तन, वर्षा के पैटर्न में परिवर्तन, बढ़ते तापमान, भूजल स्तर, मृदा की उर्वरता, पर्यावरणीय परिवर्तन, फसल विविधीकरण, बीजों की उपलब्धता, खेती की लागत, बाजार व्यवस्था तथा कृषि से संबंधित अन्य कारकों के आकलन सहित ऐसी गिरावट के कारणों का कोई वैज्ञानिक अध्ययन कराया है और यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) क्या मसूर उत्पादक किसानों के हित में बहराइच में दलहन मूल्य संवर्धन तथा गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग): राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में लेन्टिल (मसूर) का क्षेत्र और उत्पादन वर्ष 2024-25 के दौरान उत्पादन में मामूली कमी को छोड़कर वर्ष दर वर्ष बढ़ रहा है, जो निम्नलिखित है:

	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
क्षेत्रफल (हजार हेक्टेयर में)	49.01	55.73	64.90	67.66	70.13
उत्पादन (हजार टन में)	52.54	52.67	55.75	58.20	57.70

स्रोत: कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश और 3 संघ राज्य क्षेत्रों, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी सहित सभी राज्यों में अरहर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान देने के साथ दलहन के उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से "दलहन आत्मनिर्भरता मिशन" नामक एक केंद्र प्रायोजित योजना लागू कर रहा है।

दलहन मिशन के तहत, राज्य सरकारों के माध्यम से दलहन उगाने वाले किसानों को विभिन्न प्रयासों में सहायता प्रदान की जाती है जैसे कि नई जारी की गई किस्मों के बीज उत्पादन, उच्च उपज और जलवायु अनुकूलित किस्मों के प्रमाणित बीजों का वितरण, सीडकिट वितरण, नवीनतम फसल उत्पादन से जुड़ी प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन, क्षमता निर्माण और फसलोपरांत इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना। इसके अतिरिक्त, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रजनक बीजों की खरीद पर 100% केन्द्रीय सहायता दी जाती है। यह मिशन राज्यों द्वारा की गई मांग के अनुसार प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) के अंतर्गत मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के मानदंडों के अनुसार नैफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से इच्छुक और पंजीकृत किसानों से मसूर की सुनिश्चित खरीद में भी सहायता प्रदान करता है। फसलोपरांत इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, वर्ष 2025-26 से वर्ष 2030-31 की अवधि में प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए 25 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

देश में मसूर के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) आईसीएआर-भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान (आईआईपीआर), कानपुर में मसूर पर बुनियादी और रणनीतिक अनुसंधान कर रहा है। इसके अतिरिक्त, बहराइच सहित उत्तर प्रदेश में मसूर की उत्पादकता और उत्पादन में वृद्धि करने के लिए स्थान विशिष्ट, अधिक उपज देने वाली किस्मों और उपयुक्त उत्पादन प्रौद्योगिकी पैकेजों को विकसित करने के लिए राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों के सहयोग से रबी दलहन पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (एआईसीआरपी) के माध्यम से व्यावहारिक शोध किया जा रहा है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, वर्ष 2018 से बहराइच सहित उत्तर प्रदेश में खेती योग्य 20 उच्च उपज देने वाली, जलवायु-अनुकूलित मसूर की किस्मों को अधिसूचित किया गया है।

नई जारी की गई मसूर की किस्मों को अपनाने की सुविधा के लिए, पिछले तीन वर्षों के दौरान लगभग 368 क्विंटल प्रजनक बीज का उत्पादन किया गया और बहराइच सहित पूरे उत्तर प्रदेश में किसानों द्वारा उपयोग के लिए बड़ी मात्रा में प्रमाणित बीज तैयार करने हेतु बीज उत्पादक एजेंसियों को आपूर्ति की गई। इसके अलावा, मसूर की उन्नत किस्मों के गुणवत्तापूर्ण प्रमाणित बीजों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए, पिछले तीन वर्षों के दौरान लगभग 4,996 क्विंटल प्रमाणित बीजों का उत्पादन किया गया था और आईसीएआर के तत्वावधान में राज्य में स्थापित दलहन केंद्रों पर 14 बीज हब के माध्यम से उपलब्ध कराया गया था। इसके अतिरिक्त, मसूर की उन्नत किस्मों और उत्पादन प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में एआईसीआरपी से जुड़े वैज्ञानिकों ने पिछले तीन वर्षों के दौरान बहराइच सहित पूरे उत्तर प्रदेश में किसानों के खेतों पर 421 फ्रंटलाइन प्रदर्शन (एफएलडी) आयोजित किए।

राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2023-24 से वर्ष 2025-26 के दौरान उत्तर प्रदेश में मसूर के प्रमाणित/गुणवत्ता वाले बीजों की आवश्यकता और उपलब्धता निम्नानुसार है:

(बीजों की मात्रा लाख क्विंटल में)

क्र. सं.	वर्ष	माँग	उपलब्धता
1	2023-24	2.34	2.49
2	2024-25	2.63	2.80
3	2025-26	3.10	3.66

इसके अलावा, खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन इंफ्रास्ट्रक्चर (एफएसक्यूएआई) प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत एक मांग-संचालित घटक योजना है, जिसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत मंत्रालय खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के संपदा पोर्टल पर समय-समय पर जारी अभिरुचि की अभिव्यक्ति (एक्स्प्रेशन ऑफ इंटरेस्ट) (ईओआई) के माध्यम से देश भर से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। वर्तमान में, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के पास बहराइच में खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

*****